बजट 2014-15 की मुख्य विशेषताएं

मौजूदा आर्थिक हालात और चुनौतियां

- वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति ही वह अहम निर्णायक कारक है जो प्रत्येक विकासशील देश के भाग्य से जुड़ा है।
- विश्व अर्थव्यवस्था में 2011 में 3.9 प्रतिशत, 2012 में 3.1 प्रतिशत और 2013 में 3 प्रतिशत की ह्रासमान विकास दर रही है।
- भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों, जो कि हमारे विदेशी पूंजी अंतर्वाह के प्रमुख स्रोत भी हैं, की वित्तीय स्थिति तनावग्रस्त चल रही है। संयुक्त राज्य अमरीका हाल ही में लम्बी मंदी से उबरा है, समूचा यूरो जोन 0.2 प्रतिशत की विकास दर से गुजर रहा है और चीन की विकास दर भी घटी है।
- हमारे देश द्वारा झेली जा रही आर्थिक चुनौतियां उभरती हुई सभी अर्थव्यवस्थाओं की चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के बावजूद संकट के क्षणों में हमने कामयाबी हासिल की है।
- राजकोषीय समेकन के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक रहने के अलावा, मूल्य स्थिरता, खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता विकास चक्र की बहाली, बढ़ता हुआ निवेश, संवर्धित विनिर्माण और निर्यात वृद्धि, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्याप्त तनाव को कम करना 2012-13 के प्रमुख लक्ष्य थे।

अर्थव्यवस्था की स्थिति

घाटा और मुद्रास्फीति

- 2013-14 का राजकोषीय घाटा 4.6 प्रतिशत रहा।
- चालू खाता घाटा 2012-13 में 88 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर 2013-14 में 45 बिलियन अमरीकी डालर रहने का अनुमान है।
- इस वित्त वर्ष में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 15 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

- रेटिंग एजेंसियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था गिरने का कोई संकेत नहीं है।
- कार्यसूची में राजकोषीय स्थिरता पहली प्राथमिकता है।
- मुद्रास्फिति कम करने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने संयुक्त प्रयास किया।
- जनवरी, 2014 में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति घटकर 5.05 प्रतिशत और कोर मुद्रास्फीति घटकर 3.0 प्रतिशत हो गई।
- खाद्यान्न मुद्रास्फीति 13.8 प्रतिशत से घटकर 6.2 प्रतिशत पर आ गई।

कृषि

- कृषि क्षेत्र ने उल्लेखनीय कार्य किया।
- 2012-13 में 255.36 मिलियन टन की तुलना में चालू वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन 263 मिलियन टन होने का अनुमान है।

- 2012-13 में 41 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में कृषि निर्यात के 45 बिलियन अमरीकी को पार करने की संभावना।
- कृषि ऋण ₹7 लाख रुपए की सीमा पार की।
- पिछले चार वर्षों में 4.0 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष कृषि घरेलू उत्पाद दर के 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

निवेश

- 2012-13 में बचत दर 30.1 और निवेश दर 34.8 प्रतिशत रही।
- सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिए निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति और परियोजना मानीटरिंग समूह का गठन किया। जनवरी, 2014 तक ₹6,60,000 करोड़ की लागत वाली 296 परियोजनाओं को क्लीयर किया गया।

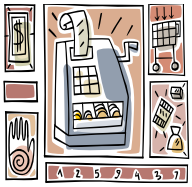

विदेश व्यापार

- वैश्विक व्यापार दर में गिरावट के बावजूद निर्यात में तीव्र वृद्धि।
- पण्य निर्यात के 326 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने का अनुमान है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 6.3 प्रतिशत को दर्शाता है।

विनिर्माण

- विनिर्माण और घरेलू व्यापार क्षेत्र में मंद निर्यात एक चिंता का विषय है।

- निवेश में मंदी के कारण विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि धीमी हुई है।
- राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र के भागीदीरी को बढ़ाने और दस वर्षों में 100 मिलियन नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरीडोर (डीएमआईसी) के साथ आठ राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड) की घोषणा की गई। डीएमआईसी ट्रस्ट द्वारा 9 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया।

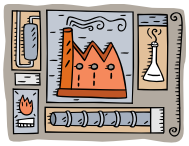

- चेन्नई और बंगलुरु, बंगलुरु और मुम्बई तथा अमृतसर और कोलकाता को जोड़ने वाले तीन अन्य औद्योगिक कोरीडोर कार्यान्वयन की तैयारी के विभिन्न चरणों में है।
- प्रमुख विनिर्माण उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता जोड़ी जा रही है।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संवर्धन के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति की अधिसूचना, प्रौद्योगिकी एवं सामान्य सुविधाओं की स्थापना और खादी मार्क की शुरुआत।

अवसंरचना

- वर्ष 2012-13 और चालू वित्त वर्ष के नौ महीनों में अवसंरचना उद्योगों को भारी बढ़ावा देने के लिए विद्युत क्षमता का 29,350 मेगावाट, 3,928 कि.मी. के राष्ट्रीय राजमार्ग 39,144 कि.मी. ग्रामीण सड़के, 3,343 कि.मी. नई रेल लाइनें और पत्तनों में 217.5 मिलियन टन की सालाना क्षमता वृद्धि की गई है।

- 19 तेल और गैस ब्लाक पर खनन कार्य चल रहा है और 7 नए विमानपत्तन निर्माणाधीन है।
- अवसंरचना परियोनजाओं के लिए वित्त पोषण मुहैया कराने के लिए अवसंरचना ऋण कोषों को बढ़ावा दिया गया है।

विनिमय दर

- मई, 2013 में आस्तियों की खरीद में यूएस फेडरल रिजर्व ऑफ रिडक्शन द्वारा दिए गए संकतों से रुपया पर दबाव।
- पूंजीगत अंतवाहों को सुकर बनाने और विदेशी विनिमय बाजारों को स्थिर करने के लिए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी के द्वारा कई उपाय किए गए। फलस्वरुप दिसम्बर, 2013 में वास्तविक कटौती के समय उदीयमान अर्थव्यवस्था वाली मुद्राओं में रुपया न्यूनतम प्रभावित रहा।

सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि

- सकल घरेलू उत्पाद मंदी जो 2011-12 में शुरु हुई थी, 2011-12 में इसी अवधि के दौरान 7.5 प्रतिशत से घटकर 2013-14 की पहली तिमाही में 4.4 प्रतिशत हो गई जिसमें सरकार द्वारा लिए गए कई उपायों को नियंत्रित किया जा सकता है। मौजूदा वर्ष के तीसरी और चौथी तिमाही में वृद्धि 5.2 प्रतिशत होने की प्रत्याशा है और पूरे वर्ष के लिए 4.9 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है।
- कम होता हुआ राजकोषीय घाटा, स्थिर विनिमय दर और चालू खाता घाटा, मुद्रास्फीति में नरमी और बढ़ता हुआ निर्यात आज की अपेक्षाकृत स्थिर अर्थव्यवस्था का प्रतिफल है।

यूपीए के विकास संबंधी कीर्तिमान

- भारत में विकास बहुत जरुरी है किंतु इसे स्थिर और समावेशी वृद्धिपूरक मॉडल का होना चाहिए और उसे पर्यावरण, अंतर पीढ़ीगत साम्यताओं और ऋणग्रस्तता जैसे समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
- यूपीए सरकारों के 10 वर्ष में असाधारण विकास रहा है।
- खाद्यान्नों का उत्पादन 213 मिलियन टन से बढ़कर 263 मिलियन टन हो गया, संस्थापित विद्युत क्षमता 1,12,700 मेगावाट से बढ़कर 2,34,600 मेगावाट हो गयी, कोयला उत्पादन 361 मिलियन टन से बढ़कर 554 मिलियन टन हो गया और 10 वर्षों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़के 51,511 कि.मी. से बढ़कर 3,89,578 कि.मी. हो गई।

- 10 वर्षों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर किया गया खर्च ₹7248 से बढ़कर ₹36,322 करोड़ हो गया।
- शिक्षा पर व्यय 10 वर्ष पहले के ₹10,145 करोड़ से ₹79,451 करोड़ पहुंचा।
- यूपीए I और यूपीए II के दौरान 6.2 प्रतिशत की विकास दर बनी रही जो कि 33 वर्षों में सर्वाधिक थी।

2013-14 का रिपोर्ट कार्ड

- चीनी को नियंत्रण मुक्त करना, डीजल मूल्यों में आंशिक संशोधन, रेल किराया का यौक्तिकीकरण, सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं।
- नए बैंक लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
- डिस्कॉम, अधिकतर रुग्ण, को उदार केंद्रीय सहायता से पुनर्संरचित किया जा रहा है।
- अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारम्परिक वनवासी अधिनियम के अधीन 18.80 लाख हेक्टेयर में 12.8 लाख भूमि पट्टे वितरित किए गए।
- उचित क्षतिपूर्ति पारदर्शिता के अधिकार के दमनात्मक औपनिवेशक कानून, 1894 के स्थान पर भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और बंदोबस्त अधिनियम।

- 67 प्रतिशत जनसंख्या/परिवारों को खाद्य सुनिश्चित कराते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया।
- 1956 के पुराने कानूनों के स्थान पर नया कम्पनी अधिनियम।
- नई पेंशन स्कीम के लिए सांविधिक विनियामक स्थापित करने के लिए पीएफआरडीए अधिनियम।

आर्थिक पहलें

- बेहतर कारगरता हेतु केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को 66 कार्यक्रमों में पुनर्संरचित किया गया था। इन कार्यक्रमों के निधियां राज्य आयोजनाओं को केंद्रीय सहायता के रुप में जारी की जाएंगी जो ज्यादा प्राधिकार और उत्तरदायित्व देंगी। इसके परिणामस्वरुप राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता 2013-14 के बजट अनुमान में ₹1,36,254 करोड़ से अत्यधिक बढ़कर 2014-15 में ₹338562 करोड़ हो जाएगीं।

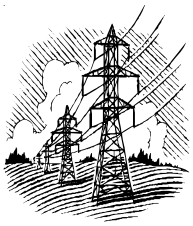

- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा 2013-14 में ₹257641 करोड़ का रिकार्ड पूंजी व्यय।
- सभी स्वीकृतियां और अनुमोदन मिलने के पश्चात ताप और पनबिजली विद्युत क्षमता का लगभग 50,000 मेगावाट निर्माणाधीन है। 78,000 मेगावाट की विद्युत क्षमता को कोयला आपूर्ति सुनिश्चित।
- भारी मात्रा में निवेश आकर्षित करने के लिए दूर-संचार, भेषज, नागर विमानन, विद्युत व्यापार विनिमय और मल्टी-ब्रांड खुदरा के लिए उदार एफडीआई नीति।
- 2 सेमी कन्डक्टर वेफर फैब यूनिटों की स्थापना का अनुमोदन।
- डाक विभाग में आईटी आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी।

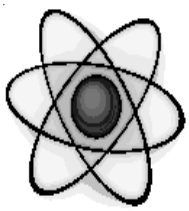

- कूडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट-I एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और 180 मिलियन यूनिट का बिजली उत्पादन।
- कलपक्कम में फास्ट ब्रिडर रिएक्टर और 7 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर निर्माणाधीन हैं।
- 2014-15 में 500 मेगावाट क्षमता वाली 4 अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना के साथ राष्ट्रीय सौर मिशन।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय निधि के कार्पस में ₹100 करोड़ के आरम्भिक अंशदान से एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमी की सहायता के लिए सामाजिक लाभ वाली जमीन से जुड़े नवोन्मेषों के संर्वधन हेतु 'भारत समावेशी नवोन्मेष निधि' सृजित की जाएगी।

सामाजिक क्षेत्र में पहल

- ₹200 करोड़ की आंरभिक पूंजी के साथ अनुसूचित जातियों के लिए संयुक्त पूंजी कोष।
- एकीकृत बाल विकास योजना की पुनर्बहाली, 400 जिलों में क्रियान्वयन और शेष जिलों को 1.4.2014 तक कवर कर लिया जाएगा।
- राष्ट्रीय कृषि-वानिकी नीति 2014 को मंजूरी।
- गौण वनोत्पाद के विपणन के लिए मेकनिज्म तैयार किया गया है और 2014-15 में इस स्कीम ने ₹444.59 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के विकास के लिए ₹100 करोड़ में आवंटन के साथ एक नई स्कीम।
- जेई टीके जो कि थैलिसिमिया की नैदानिक जांच की एक नई तकनीक है और सर्वाइकल कैंसर पता लगाने में मैग्नीवियुलाइजर जन साधारण को समर्पित।

कुछ राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता

- इस वित्त वर्ष में पूर्वोत्तर राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को ₹1200 करोड़ की राशि की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता।

अंतरिक्ष

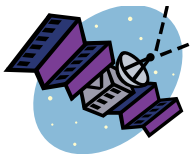

- मंगल आर्बिटर मिशन के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल है।
- देश ने वाहन तकनीक, कार्योजनिक, नेवीगेशन, मेट्रोलॉजिकल तथा संचार उपग्रहों प्रक्षेपण की क्षमता।
- 2014-15 के लिए कई परीक्षण उड़ाने, नेवीगेशन सैटेलाइट और अंतरिक्ष मिशनों की योजना।

पुराने वायदे

- ₹1000 करोड़ नॉन लैप्सेबल आंरभिक निर्भया कोष तैयार किया गया। महिलाओं की सुरक्षा और उनकी गरिमा सुनिश्चित करने के लिए दो प्रस्तावों का अनुमोदन किया जिनका वित्तपोषण निर्भया ऋण से किया जाएगा। 2014-15 में इसमें ₹1000 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी।
- ₹1000 करोड़ के आवंटन के साथ अगस्त 2013 में राष्ट्रीय कौशल अभिप्रमाणन और मौद्रिक पुरस्कार स्कीम ने काफी सफलता हासिल की है। इसके कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए इसमें ₹1000 करोड़ की अतिरिक्त राशि अंतरित की जा रही है।
- सरकार आधार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जिसके तहत वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ₹57 करोड़ यूनीक नम्बर जारी किए गए हैं और सभी आधार धारकों का बैंक खाता खुलवाया गया है।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम (डीबीटी) के द्वारा 27 स्कीमों के तहत, 31 जनवरी, 2014 तक कुल ₹628 करोड़ (₹54,20,114) का अंतरण सीधे लाभार्थियों को किया गया।

अंतरिम बजट का अवलोकन

- योजना व्यय को बनाए रखने के लिए इसे 2014-15 में भी 2013-14 के स्तर पर रखा गया है।

- जो मंत्रालय/विभाग महत्वपूर्ण फ्लैगशिप कार्यक्रम चलाते हैं उन्हें 2014-15 में या तो 2013-14 के बराबर अथवा उससे अधिक समुचित निधियां उपलब्ध कराई गई। इनमें ये मंत्रालय शामिल हैं: अल्पसंख्यक मामले, जनजातीय मामले, आवास और गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, पंचायत राज, पेयजल और स्वच्छता, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, मानव संसाधन विकास और ग्रामीण विकास।

रेलवे

- रेलवे को बजटीय सहायता बजट अनुमान 2013-14 में ₹26,000 करोड़ से बढ़ाकर 2014-15 में ₹29,000 करोड़ की गई।

- रेलवे का परियोजनाओं के लिए निधियां जुटाने हेतु नई लिखतों और नए तंत्रों को अभिचिन्हांकित करने का प्रस्ताव है।

अनुसूचित जाति उप-योजना और अनुसूचित जनजाति उप-योजना, महिलोन्मुखी बजट और बाल विकास

- अ. जा. उप योजना और अ.ज.जा. उप-योजना को क्रमशः ₹48,638 करोड़ और ₹30,726 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- महिलोन्मुखी बजट और बाल बजट के लिए क्रमशः ₹97,533 करोड़ और ₹81,024 करोड़।

आयोजना-भिन्न व्यय

- आयोजना-भिन्न व्यय ₹ 1207,892 करोड़ अनुमानित।
- खाद्य, उर्वरक और ईंधन हेतु सब्सिडी पर व्यय 2013-14 के ₹2,45,453 करोड़ के संशोधित अनुमान से थोड़ा अधिक ₹2,46,472 करोड़ होगा।
- देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु सरकार की दृढ़ और अटल वचनबद्धता को देखते हुए खाद्य सब्सिडियों के लिए ₹1,15,000 करोड़ आवंटित।

रक्षा

- ब.अ. 2013-14 की तुलना में रक्षा आवंटन में 10 प्रतिशत वृद्धि की गई है।
- रक्षा बलों के लिए एक रैंक एक पेंशन के सिद्धांत को सरकार ने मान लिया है, जिसे संभवतः वित्त वर्ष 2014-15 से लागू किया जाएगा। मौजूदा वित्त वर्ष में ही रक्षा पेंशन खाते में ₹500 करोड़ अंतरित करने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल

- केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की क्षमता बढ़ाने और उन्हें अत्याधुनिक उपकरण एवं प्रौद्योगिकी मुहैया कराने हेतु ₹11,009 करोड़ की आधुनिकीकरण योजना का अनुमोदन किया गया है।

वित्तीय सेक्टर

- फरवरी, 2013 के बजट भाषण में की गई सभी वित्तीय सेक्टर संबंधी घोषणाएं लागू की गई हैं।
- पब्लिक सेक्टर बैंकों में पूंजी लगाने की व्यवस्था करने के लिए ₹11,300 करोड़ का प्रस्ताव है।
- 8,023 के लक्ष्य की तुलना में 5,207 नई शाखाएं खोली गई हैं।

- भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई है।
- ग्रामीण और शहरी आवास हेतु क्रमशः ₹6,000 करोड़ और ₹2,000 करोड़ दिया गया है।
- कृषि ऋण के ₹7,00,000 करोड़ के लक्ष्य को बैंकों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। 2014-15 हेतु ₹8,00,000 करोड़ का लक्ष्य है।
- फार्म ऋणों पर ब्याज सहायता स्कीम के अंतर्गत ₹23,924 करोड़ जारी किया गया है, फार्म ऋणों पर 4 प्रतिशत ब्याज दर लागू है, जिसमें ब्याज सहायता 2 प्रतिशत और तुरन्त भुगतान हेतु 3 प्रतिशत शामिल है।

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण

- ❑ अल्पसंख्यकों के बैंक खातों की संख्या 14,15,000 से बढ़कर 43,52,000 हो गई और 10 वर्षों की अवधि में ऋण देने की मात्रा ₹4,000 करोड़ से बढ़कर ₹66,500 करोड़ हो गई है।
- ❑ दिसम्बर, 2013 की समाप्ति पर, ₹ 2,11,451 करोड़ ऋण अल्पसंख्यकों को दिया गया।

स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) ऋण

- ❑ दस वर्ष पहले केवल-महिला स्वयं-सहायता समूह बैंकों के ऋण से जुड़ी थी। दिसंबर, 2013 के अंत में ₹4,11,6000 महिला एसएचजी को ऋण दिया गया है और ऋण की बकाया राशि ₹36,893 करोड़ थी।

शिक्षा ऋण

- ❑ दिनांक 31.3.2009 तक लिए गए और 31.12.2013 तक बकाया सभी शिक्षा ऋणों के लिए छूट अवधि का प्रस्ताव। सरकार 31.12.2013 को बकाया ब्याज की देनदारी का दायित्व लेगी परन्तु उधारदाताओं को 1.1.2014 के बाद की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करना होगा। इस वर्ष यह लगभग 9 लाख विद्यार्थियों को ₹2,600 करोड़ लाभ पहुंचाएगा।

बीमा

- ❑ जीवन बीमा निगम और चार सरकारी क्षेत्र की जनरल इन्श्यूरेंस कंपनियों ने 10,000 अथवा इससे अधिक की जनसंख्या वाले कस्बों में सेवा देने के लिए परी-शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगभग 3000 कार्यालय खोले हैं।

वित्तीय बाजार

- ❑ भारतीय वित्तीय बाजार को मजबूत करने के लिए परिकल्पित उपायः
  - एडीआर/जीडीआर स्कीम का नवीकरण, निक्षेपागार प्राप्तियों का विस्तार।
  - रुपया मूल्यवर्गित कारपोरेट बांड मार्केट रूपए का उदारीकरण।
  - विदेशी करेंसी के जोखिम से भारतीय कंपनियों को पूर्णतया बचाने में समर्थ बनाने के लिए करेंसी व्युत्पन्न बाजार को ठोस व सुदृढ़ बनाना।
  - प्रत्येक व्यक्ति की सारी वित्तीय परिसंपत्तियों का एक रिकार्ड बनाना।
  - भारतीय बांडों में निवेश के इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को प्रवाही समाशोधन निपटान में समर्थ बनाना।

कमोडिटी व्युत्पन्न बाजार

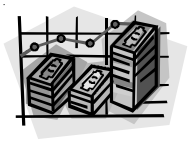

- ❑ एनएसईएल में भुगतान संकट के बाद नेशनल स्पाट एक्सेचेंज को अपने अधिकार में लेने की त्वरित कार्रवाई। इसने वित्तीय बाजार के अन्य विनियमित संघटकों में संकट फैलने से बचाया।
- ❑ वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव।

महत्वपूर्ण लंबित विधेयक

- ❑ बीमा कानून (संशोधन) विधेयक और प्रतिभूति कानून (संशोधन) विधेयक, उन कारणों, जिनका विधेयक के गुणदोष से कोई संबंध नहीं है, संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है।

सरकारी ऋण प्रबंधन एजेंसी

- ❑ सरकारी ऋण प्रबंधन एजेंसी विधेयक सरकार के पास तैयार है। प्रस्ताव है कि गैर-सांविधिक पीडीएमए स्थापित किया जाए जो 2014-15 में कार्य कर सके।

भावी योजनाएं

- ❑ वैश्विक अर्थव्यवस्था में अग्रणी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए भारत, अमरीका और चीन के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार।

- ❑ भावी रोडमैप के भाग के रूप में 10 कार्य
  - राजकोषीय समेकनः हमें 2016-17 तक सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त करना और सदैव उस स्तर से नीचे रहना।
  - चालू खाताः चालू खाता कुछ और वर्षों के लिए अवश्यंभावी होगा जिसे केवल विदेशी निवेश द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। अतः, विदेशी निवेश के निवारण के लिए कोई स्थान नहीं है।
  - मूल्य स्थिरता और विकासः विकासशील अर्थव्यवस्था में, उच्च विकास लक्ष्य मुद्रास्फीति के नियंत्रित की मांग करती हैं। मौद्रिक नीति तैयार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक को मूल्य स्थिरता तथा विकास के बीच संतुलन रखना चाहिए।
  - वित्तीय क्षेत्र सुधार पूरे किए जाने होंगे जैसाकि वित्तीय क्षेत्र सुधार आयोग ने निर्धारित किया है।
  - अवसंरचना में व्यापक निवेशः सरकारी निजी भागीदारी के जरिए जुटाया जाएगा।

  - विनिर्माण क्षेत्र भारत के विकास का आधार होगाः केन्द्रीय तथा राज्य के सभी कर जो निर्यातित उत्पाद पर लगते हैं,माफ करने चाहिए अथवा उन पर छूट दी जानी चाहिए। घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए न्यूनतम टैरिफ सुरक्षा हो।
  - सिब्सिडियां जो बिल्कुल जरूरी हैं, केवल पूरी तरह से पात्र होने पर चुनी जानी चाहिए तथा लक्ष्यगत की जानी चाहिए।
  - शहरों को शासन योग्य तथा रहने योग्य बनाने के लिए शहरीकरण का प्रबंध किया जाना है।
  - कौशल विकास को माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा, स्वच्छता तथा सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के बराबर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  - राज्यों को विकास में भागीदार बनाना ताकि केन्द्र को रक्षा, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा दूरसंचार पर ध्यान देने के लिए सक्षम बनाया जाए।

राजस्व

जीएसटी तथा डीटीसी

- ❑ सरकार 2014-15 में जीएसटी कानूनों तथा प्रत्यक्ष कर संहिता को पारित करने का समाधान करने हेतु सभी राजनैतिक पार्टियों से अपील करती है।

वैज्ञानिक अनुसंधान का निधियन

- ❑ अनुसंधान निधियन संगठन की स्थापना का प्रस्ताव है जो प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के जरिए चयनित अनुसंधान परियोजनाओं को धन प्रदान करेगा। इस संगठन में अंशदान कर लाभों का पात्र होगा। अपेक्षित विधायी परिवर्तन नियमित बजट के समय प्रारंभ किए जा सकते हैं।

विदेशी खाते

- ❑ सरकार 67 मामलों में भारतीय के गैर-कानूनी विदेशी खातों के बारे में सूचना प्राप्त करने में सफल रही है और इस पर कार्रवाई चल रही है। 17 अन्य मामलों में जानबूझकर कर चोरी के लिए अभियोजन भी शुरू किया है। भारतीय व्यक्तियों के सूचित खातों में कर विहीन अथवा कम कर अधिकार क्षेत्रों में अधिक पूछताछ प्रारंभ की गई है।

कर की दरों में परिवर्तन

- ❑ कुछ प्रत्यक्ष कर दरों में निम्नलिखित परिवर्तन प्रस्तावित हैं:

  - राज्यों को विकास में भागीदार बनाना ताकि केन्द्र को रक्षा, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा दूर संचार पर ध्यान देने के लिए सक्षम बनाया जाए।
  - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची के अध्याय 84 और 85 के अंतर्गत आने वाले सभी समानों पर उत्पाद शुल्क 30.6.2014 तक की अवधि के लिए 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया है। नियमित बजट के समय दरों में संशोधन किया जा सकता है।
  - ऑटोमोबाइल उद्योग को राहत देने के लिए जिसमें अभूतपूर्व नकारात्मक विधि हो रही है, 30.6.2014 तक की अवधि के लिए उत्पाद-शुल्क में निम्नानुसार कटौती की जाती है:

    छोटी कारें, मोटर साइकल, स्कूटर और व्यवसायिक वाहन - 12% से 8%

    एसयूवी - 30% से 24%

    बड़ी और मध्य श्रेणी की कारें - 27%/24% से 24%/20%

  - चैसिस और ट्रेलर पर उत्पाद-शुल्क में उपयुक्त कटौती करने का भी प्रस्ताव है-नियमित बजट के समय दर में संशोधन किया जा सकता है।
  - मोबाइल हैंडसेट के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सभी श्रेणी के मोबाइल हैंडसेट के लिए उत्पाद शुल्क की पुनःसंरचना की गयी है। दरें सेनवेट क्रेडिट सहित 6% या सनवेट क्रेडिट के बिना 1% होगी।
  - साबून और रंगीन रसायन के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य-भिन्न ग्रेड के औद्योगिक तेलों और इनके अंशों वसायुक्त एसिड वसायुक्त एल्कोहल पर सीमाशुल्क संरचना का 7.5 प्रतिशत पर यौक्तिकीकरण किया गया है।
  - विशिष्ट सड़क निर्माण मशीनरी के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उसी प्रकार की आयातित मशीनरी को सीवीडी से छूट समाप्त की गई है।
  - बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयातित पूंजी सामग्री पर 5% की रियायती सीमा-शुल्क प्रदान किया गया है ताकि करेंसी नोट के मुद्रण हेतु प्रतिभूति कागज के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके।

- ❑ चावल का लदान और उतराई, भंडारण और भांडागारण को सेवा कर से छूट दी गई है।
- ❑ कोर्ड ब्लड बैंकों द्वारा दी जाने वाली सेवा को सेवा कर से मुक्त रखा गया है।

बजट अनुमान

- ❑ चालू वित्त वर्ष 4.6 प्रतिशत पर राजकोषीय घाटे (4.8 प्रतिशत की निर्णायक रेखा) और 3.3 प्रतिशत पर राजस्व घाटे के चलते संतोषजनक उपलब्धि के साथ समाप्त होगा।

- ❑ वर्ष 2014-15 में राजकोषीय घाटा 4.1 प्रतिशत पर अनुमानित जो नए समेकन मार्ग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से नीचे होगा और राजस्व घाटा 3.0 प्रतिशत पर अनुमानित।

- ❑ आयोजना-व्यय का अनुमान ₹5,55,322 करोड़। आयोजना-भिन्न व्यय ₹12,07,892 करोड़ अनुमानित।

*''**वेलअनरु वेन्ड्री थरुवदु मन्नवन, कोलदुगू कोडत्तु इन्न**''*
(भाले-बरछे नहीं, बल्कि सिर्फ समता और बराबरी से युक्त सत्ता ही राजा को असली विजय दिलाती है)।

संत तिरुवल्लुवर